



प्रसंगवश

क्या बिहार में सुशासन अब जंगलराज में बदल रहा है?

ललित गर्ग

बिहार में एक बार फिर कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ अपराधियों का आतंक, दिन-दहाड़े हत्याएं, लूट, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध यह संकेत दे रहे हैं कि 'सुशासन बाबू' के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का प्रशासन कहीं अपने वादों और आदर्शों से भटकता नजर आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक के बीच आमजन में यह सवाल तेजी से उभर रहा है कि क्या बिहार में सुशासन अब फिर से जंगलराज में तब्दील हो रहा है? क्योंकि व्यापारियों, राजनेताओं, वकीलों, शिक्षकों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर की गई लगातार हत्याओं ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पुलिस इन घटना के लिए अवैध हथियारों और गोला-बारूद की व्यापक उपलब्धता को ज़िम्मेदार ठहरा रही है, पुलिस के उच्च अधिकारियों के कुछ बेतुके बयान हास्यास्पद एवं शर्मनाक होने के साथ चिन्ताजनक है। उनके हिसाब से जून में ज्यादा वारदात होती हैं, क्योंकि मानसून आने के पहले तक किसान खाली बैठे होते हैं। राज्य की राजधानी पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिनदहाड़े 5 शूटर्स ने जिस तरह एक गैंगस्टर की हत्या की, उससे यही लगता है कि कानून-व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है। पिछले 10 दिनों में एक के बाद एक कई अपराधिक घटनाओं में व्यापारी गोपाल खेमका, भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार, एक 60 वर्षीय महिला, एक दुकानदार, एक वकील और

एक शिक्षक सहित कई हत्याओं ने चुनावी राज्य को हिलाकर रख दिया है। बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजनीतिक घमासान चरम पर है। विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं एनडीए इन मुद्दों पर जवाबी एवं रक्षात्मक हमला करते हुए चुनाव पर इनके असर को बेअसर करने में जुटी है। लालू यादव के शासनकाल के 'जंगलराज' की भी याद दिलाने की कोशिश एनडीए की पार्टियां कर रही है ताकि विपक्ष इन मामलों पर ज्यादा हावी ना हो। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बिहार की जनता लालू राज में जो जंगलराज था, उसे भूली नहीं हैं। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए बिहार में आज सुशासन का राज है और जो घटनाएं हुई हैं वह योजनागत अपराध के तहत है, जिस पर सरकार कड़ी करवाई कर रही है।' हॉस्पिटल में जिसकी हत्या हुई, वह खुद हत्या के मामले में जेल में बंद था और फिलहाल पैराल पर बाहर आया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वारदात में विरोधी गैंग शामिल हो सकता है। इसका मतलब कि राज्य में संगठित अपराध फिर सिर उठा रहा है। इसी महीने, 4 जुलाई को बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसमें भी भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी हत्याएं बार-बार हो रही हैं, यह सिलसिला कहीं रुकता नहीं दिख रहा। पक्ष एवं विपक्ष के राजनीतिक दल एवं नेता चाहे जो बयान दें, लेकिन बिहार में अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, आम जनता में भय एवं असुरक्षा व्याप्त है। हाल ही में राजधानी

पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और गया जैसे प्रमुख शहरों में हुई हत्या और डकैती की घटनाएं न केवल भयावह हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि अपराधी अब पुलिस और प्रशासन से नहीं डरते और पुलिस का अपराधियों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। सड़क पर चल रहे आम लोगों को दिनदहाड़े गोली मार दी जाती है, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बिहार भले अपराध में कई दूसरे राज्यों से पीछे दिखता हो, लेकिन सच यही है कि आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। राज्य में ये अपराध तब हो रहे हैं, जब पूरा फोकस क्राइम कंट्रोल पर है। बिहार में पिछले तीन वर्षों में अपराध दर में निरंतर वृद्धि हुई है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, और लूट जैसे संगीन अपराधों में राज्य शीर्ष स्थानों में शामिल हो गया है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि चुनावी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है।

एक समय था जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर उल्लेखनीय सुधार किए थे। लालू-राबड़ी शासन के समय जिसे जंगलराज कहा जाता था, उसके मुकाबले एक उम्मीद जगी थी कि बिहार अब विकास, सुरक्षा और शांति की राह पर है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जनता फिर से असुरक्षा, भय और अराजकता के वातावरण में जीने को मजबूर है। इन स्थितियों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सरकार के पास प्रशासनिक अनुभव है, गठबंधन के रूप में राजनीतिक ताकत है, तो फिर अपराधियों पर लगातार क्यों नहीं लग पा रही है?

हाल के अपराधों की घटनाओं ने विपक्ष को सरकार की नाकामी उजागर करने का मौका दिया है, जबकि भाजपा और जनसुरक्षा रक्षक रुख अपना रहे हैं और इन घटनाओं को योजनागत घटनाओं का नाम देकर राजद सरकार के समय की अपराधिक घटनाओं के साथ तुलना कर रहे हैं। मगर सूत्रों की माने तो पार्टी इस बात को लेकर तैयारी जरूर कर रही कि, यदि यह मुद्दा संसद के आगामी सत्र में विपक्ष उठाती है तो उस पर कैसे जवाब देना है? जिस बिहार के पूर्ववर्ती सरकारों के कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति को मुख्य मुद्दा बनाकर एनडीए सरकार सत्ता में आई थी अब यही मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस कदम चाहिए, न कि केवल वादों की झड़ि। विपक्ष इस समय सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी में है और 'बदलाव कानून-व्यवस्था' को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहा है।

आरजेडी-कांग्रेस भाजपा और नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जिनके शासन में कभी सुशासन की मिसाल दी जाती थी, अब वही शासन अपराधियों के आगे बेबस नजर आ रहा है। बिहार के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। सरकार को चाहिए कि वह पुलिस-प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करे। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिले।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर

● विपक्ष बोला- वजह स्वास्थ्य ही नहीं कुछ और भी है

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। यह जानकारी राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने दी। धनखड़ आज सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। सुबह 11 बजे अपर सदन की कार्यवाही

की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश ने की। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। उधर,



पीएम मोदी ने कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 74

● संसद नहीं पहुंचे, विदाई समारोह से भी बना ली दूरी

साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उन्होंने 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था, ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त, 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। राष्ट्रपति को लिखे त्यागपत्र में धनखड़ ने पद छोड़ने की वजह स्वास्थ्य बताया था। दूसरी-विपक्ष इस्तीफे पर सवाल कर रहा है। कह रहा है कि इसकी वजह कुछ और है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

‘सांख्यिकी से समृद्धि’ के लिए ‘डाटा सुदृढ़ीकरण योजना’ को दी स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों का समयावधि में संकलन ('डाटा सुदृढ़ीकरण योजना' की स्वीकृति प्रदान की गयी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 'सांख्यिकी से समृद्धि' की दिशा में एक नई पहल कर रही है।

योजना से सरकार को डाटा के आधार पर बेहतर और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही डाटा और उसका विश्लेषण समय पर मिलने से सरकार बेहतर नीति बना सकेगी। समस्त विभाग बिना किसी रूकावट के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को भी डाटा उपलब्ध होगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण आसान होगा। नागरिकों को भी डाटा की जानकारी मिल सकेगी, जिससे शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। डाटा की उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।



गांधीसागर जल विद्युत गृह की इकाइयों के नवीनीकरण का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित (5×23) मेगावाट गांधीसागर एवं (4×43 मेगावाट) राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए मध्यप्रदेश द्वारा देय राशि का अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्णय अनुसार गांधीसागर जल विद्युत गृह की पांचों इकाइयों (5×23 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित अनुमानित लागत 464 करोड़ 55 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की चारों इकाइयों (4×43 मेगावाट) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की डी.पी.आर. में वर्णित अनुमानित लागत 573 करोड़ 76 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजना राशि पर निर्धारित अंशपूर्जी को मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्य द्वारा 50:50 अनुपात पर वित्त विभाग के परामर्श अनुसार मध्यप्रदेश की हिस्से की राशि 127 करोड़ 6 लाख रुपये को वर्षवार प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया। मशीनरी बदलने के लिए राशि का व्यय होगा। परियोजना अगले 40 साल के लिए उपयोगी है दोनों प्रदेश कि विद्युत् उत्पादन कंपनियों अपने-अपने राज्य में स्थित परियोजना का क्रियान्वयन करेगी एवं कार्यों की लागत का लेखा-जोखा पारदर्शी रूप से संचालित कर एक दूसरे से साझा करेगी तथा मौजूदा प्रथा के अनुसार वित्तीय खातों का तिमाही/वार्षिक मिलान कर समायोजित करेगी।

सुप्रभात

मैं जानना चाहता हूं
आदमी आदमी से
क्यों लड़ता है

मैं जानना चाहता हूं
आदमी
झूठ की राह पर
क्यों चलता है

मैं जानना चाहता हूं
आदमी
राजा से क्यों
इतना डरता है

मैं जानना चाहता हूं
आदमी
क्यों नफरत का जहर
पीता है

मैं जानना चाहता हूं
आदमी आदमी से
क्यों नजदीकी बनाना
नहीं चाहता।

– दुर्गाप्रसाद झाला

19 सितंबर को होगा रिटायर

1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ, 3 जंग में शामिल रहा, अब तक 400 से ज्यादा क्रैश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना में 62 सालों तक सर्विस देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। मिग-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था यानी ये आवाज की गति (332 मीटर प्रति सेकेंड) से तेज उड़ सकता था। फाइटर जेट की आखिरी 2 स्क्वाड्रन (36 मिग-21) राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात है। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23



फाइटर प्लेन को 'उड़ता ताबूत' और 'विडो मेकर' कहा जाता है। भारत ने कुल 850 से ज्यादा मिग-21 फाइटर जेट खरीदे थे। इनमें से करीब 660 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देश में ही बनाए।

स्क्वाड्रन पैथर्स के नाम से जाना जाता है। मिग-21 जेट ने 1965 के भारत-पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसकी जगह तेजस एलसीए1ए फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 400 से ज्यादा मिग-21 विमान क्रैश हुए हैं। इसमें 200 से ज्यादा पायलट मारे गए गए हैं। इसी वजह से

राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधान की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर ली। राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कोर्ट में यह याचिका तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने दायर की थी। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 28 नवंबर, 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दायित्व की।

‘हम शर्मिंदा हैं’, किशोरी को जलाने पर ‘सुप्रीम’ चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में 15 साल की नाबालिग को ज्वां जलाए जाने की घटना पर कहा, 'हम शर्मिंदा हैं।' जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयिमाल्य बागची की बेंच ने सोमवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों की स्कूलों लड़कियों, घरेलू महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और



सभी पक्षों से ठोस सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। इससे पहले, 12 जुलाई को ओडिशा के ही बालासोर जिले के फकीर मोहन कॉलेज में छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। छात्रा ने कॉलेज फैकल्टी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दी थी।

शहीद एमपी के हरिओम का हुआ अंतिम संस्कार



● राजगढ़में बेटे की पार्थिव देह को देख बेसुध हुए पिता, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि

भोपाल (एजेंसी)। लद्दाख के लेह में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए मध्यप्रदेश के राजगढ़ के अग्निवीर हरिओम नागर (22) का अंतिम संस्कार मंगलवार को पैतृक गांव दूटियाहेड़ी में हुआ। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद बेटे की पार्थिव देह को देख पिता दुर्गा प्रसाद नागर बेसुध हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। वे रोते बिलखते रहे। शहीद हरिओम नागर की पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई बालचंद्र नागर ने मुखाग्नि दी। सुबह करीब 9.30 बजे सेना के वाहन से बोड़ा नाका पर पार्थिव

सुखोई हॉक-जगुआर के लिए बनेगा एंटी ग्रेविटी सूट

● लड़ाकू विमान पायलट्स का 'सुरक्षा कवच' कानपुर में होगा तैयार

कानपुर (एजेंसी)। देश में पहली बार सुखोई हॉक, तेजस और मिराज जैसे फाइटर जेट के पायलटों के लिए एंटी ग्रेविटी सूट का निर्माण होने जा रहा है। पायलटों के लिए कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) की इकाई आयुध पैराशूट निर्माण (ओपीएफ) में एंटी ग्रेविटी सूट बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सूट देश में पहली बार बनेंगे। अभी तक एंटी ग्रेविटी सूट यूरोपीय देशों से मंगाए जाते थे। निर्माण को लाइसेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की मंजूरी मिल गई है। डीआरडीओ की रिसर्च लैब डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेट्री (डीईबीईएल) बेंगलुरु को सूट का सैपल तैयार करके भेजा जाएगा। इसके बाद इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। दरअसल कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम में पायलट को ग्रेविटी सूट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस, ऑक्सीजन से लैस किया जाता है। फाइटर जेट काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। पायलटों को तंग मोड़, तेज चढ़ाई और अन्य आक्रामक उड़ान युद्धाभ्यास करते समय अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालातों में खून निचले अंगों में जमा हो जाता है। जिसकी वजह से मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। इस दौरान पायलटों को कम दिखना या चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बचाव के लिए डीआरडीओ की रिसर्च लैब डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेट्री (डीईबीईएल) तैयारी में जुट गया है। पायलटों के पेट और निचले अंगों पर नियंत्रित दबाव डालकर इस प्रभाव को कम करने एंटीजी सूट विशेष रूप से डिजाइन किया है। यह दबाव महत्वपूर्ण अंगों खासकर मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। जिससे पायलट की सुरक्षा और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। खास बात यह कि यह सूट आग से भी सुरक्षित रखता है। इसकी ब्लैडर प्रणाली पॉलिथेन लेपित कपड़ों से बनी है। जो रासायनिक क्षरण के प्रति बेहतर प्रतिरोध और लंबी उड़ान में सहायक बनती है।

वोटर लिस्ट से अयोग्य लोगों को हटाने के लिए एसआईआर जरूरी

ईसी ने कहा-आधार,वोटर आईडी और राशन कार्ड पर नहीं कर सकते भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया जा रहा है। वोटरों को वोट से वंचित करने का आरोप लगाकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची में छेड़छाड़ के उन आरोपों का खंडन किया है। बिहार में एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आयोग ने कहा कि वह है, जिससे मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं, आयोग ने कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दृष्टया मत से असहमति जताई। चुनाव आयोग ने न्यायालय से कहा कि इन पर जाएगा। हालांकि, चुनाव आयोग ने जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम न होने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। देर शाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक विस्तृत हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी कानून और मतदाता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। साथ ही, उसने अदालत से 11 विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों और बिहार के कुछ निवासियों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया, जिसमें एसआईआर को रद्द करने और दिसंबर में संशोधित पिछली मतदाता सूची के आधार पर नवंबर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की गई थी।

चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में घायल

● बिहार एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा तो फायरिंग की ● भागने में मदद करने वाला अभिषेक भी हो गया गिरफ्तार



आरा (एजेंसी)। बिहार के आरा में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। एक को गिरफ्तार किया गया है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ को गैंगस्टर मर्डर केस से जुड़े 3 अपराधियों बलवंत, रवि रंजन और अभिषेक के बिहियां थाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। टीम ने मंगलवार सुबह 5 बजे कटिया रोड के पास उन्हें घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बलवंत और रवि

युवाओं और बहनों के रोजगार के लिए राज्य सरकार संकल्पित

अचारपुरा में 24 जुलाई को होगा पांच इकाइयों का भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं और बहनों के रोजगार के लिए संकल्पित है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार 24 जुलाई को भोपाल जिले के औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में पांच औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने हाल ही में स्पेन और दुबई की यात्रा में अनेक निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष है। गांव से लेकर शहरों तक समृद्धि लाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निर्णायक भूमिका निभा कर मध्यप्रदेश ने नए औद्योगिक युग की शुरुआत की है।

पांच इकाइयों का होगा भूमि-पूजन- मुख्यमंत्री डॉ. यादव 24 जुलाई को अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 12.88 हेक्टेयर में 400 करोड़ से अधिक निवेश और लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 5 इकाइयों का भूमि-पूजन करेंगे। इनमें गारमेट सेक्टर में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर में इंडो एर्कोई अपरेल्स, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में एसेडस प्राइवेट लिमिटेड, फार्मा सेक्टर में सिनाई हेल्थ केयर और कृषि उपकरण में समर्थ एग्रीटेक इकाइयां शामिल हैं।

स्टार कास्ट के साथ 'तन्वी द ग्रेट' देखने पहुंचे सीएम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री निवास के समलभ भवन में जाने-माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री अनुपम खेर ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अनुपम खेर का अंग वस्त्र से सम्मान किया। श्री खेर भोपाल में फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के विशेष प्रदर्शन के अवसर पर आए हैं। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री सुश्री शुभांगी दत्त और बाल कलाकार विराज अग्रवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभिनेता खेर और उनकी टीम को एक श्रेष्ठ उद्देश्य पूर्ण फिल्म के निर्माण के लिए बधाई दी। श्री अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपनी अपनी पुस्तक डिफरेंट बट नो लैस भी भेंट की। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिनेपॉलिस के कर्मचारियों से बातचीत की और उनके कामकाज की जानकारी ली।

मात्र स्वच्छता क्षेत्र में निरंतर रहेगा आगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भोपाल की महापौर श्रीमती राय ने की भेंट

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार की शाम मंत्रालय में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्रीमती राय ने राष्ट्रपति द्वारा भोपाल को स्वच्छता क्षेत्र में दिये गये प्रशस्ति पत्र एवं ट्राफी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महापौर श्रीमती मालती राय सहित नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी, श्री रविंद्र याति, श्री राजेश हिंगोयनी और अन्य पदाधिकारी गण को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल, इंदौर सहित मध्यप्रदेश के अन्य शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों से गत सप्ताह सम्मानित किया। भोपाल को 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में स्वच्छ शहर का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से बुधनी नगर निकाय के पदाधिकारी गण ने भी भेंट की



और 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बुधनी के पुरस्कृत होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दोनों निकायों के पदाधिकारियों को बधाई दी। महापौर श्रीमती मालती राय ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भोपाल नगर के सफाई मित्रों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।

मालदीव की आजादी के जश्न में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी

माले (एजेंसी)। मोहम्मद मुइज्जु के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दो दिवसीय मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। वह मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह के जश्न में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 25 और 26 जुलाई को मालदीव में रहेंगे। राष्ट्रपति मुइज्जु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव आने का न्योता दिया था। अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाना इस बात की ओर संकेत करता है कि मालदीव और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। वहीं मालदीव को अपनी पिछली गलतियों का अहसास भी हो गया है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। मुक्त व्यापार समझौते से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी पहले चरण में दो दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे और फिर मालदीव की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की 25 से 26 जुलाई तक होने वाली मालदीव यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रतीक है। चीन समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज्जु के नवंबर 2023 में सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी 23 से 24 जुलाई को ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टर्मर के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन ने समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। मई में भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया था, जिससे 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को टैरिफ से लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में किस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात आसान हो जाएगा, साथ ही समग्र व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन द्वारा किए गए सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साथ-साथ, दोनों पक्षों ने दोहरे योगदान समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह भारतीय कामगारों के नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से छूट प्रदान करता है। अधिकारियों के अनुसार, तीन वर्षों की बातचीत के बाद तय हुए इस व्यापार समझौते से सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है और भारत को लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइन (उत्पाद श्रेणियों) पर टैरिफ हटने से लाभ होगा, जो लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्यों को कवर करेगा।

इंदौर के सभी वार्डों में एससी-एसटी आरक्षण का रोटेशन नहीं, ओबीसी वार्डों का ही होगा

तीन साल पुराने आदेश को निरस्त कर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला पलटा



इंदौर। हाईकोर्ट ने सोमवार को इंदौर नगर निगम के वार्ड आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि शहर के सभी 85 वार्डों में एससी-एसटी के लिए आरक्षित वार्ड अब स्थायी रहेंगे। अर्थात् उन्हें चुनाव के समय

बदला नहीं जाएगा। रोटेशन सिर्फ ओबीसी वर्ग की सीटों पर ही लागू होगा। राज्य सरकार की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का पुराना आदेश रद्द करने का फैसला दिया। तीन साल पहले जयेश गुरनानी ने याचिका दायर कर एससी-एसटी के आरक्षित वार्डों में भी ओबीसी की तरह रोटेशन की मांग की थी। उनकी दलील थी, कि आरक्षण स्थायी नहीं होना चाहिए, ताकि अन्य वर्गों को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले। इस याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने निर्णय देते हुए रोटेशन की बात मान ली थी। सिंगल बेंच के इस आदेश को राज्य

सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। सरकार ने तर्क दिया कि आरक्षण तय करना सरकार का विशेषाधिकार है। एससी-एसटी वर्ग के वार्डों को स्थायी आरक्षण में रखना सरकार की नीति का हिस्सा है, यह निर्णय कानून के दायरे में है।

सरकार के पक्ष में सुनाया हाई कोर्ट ने फैसला

डिवीजन बेंच में सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही माना और कहा कि ओबीसी के लिए रोटेशन लागू रहेगा। लेकिन, एससी-

एसटी के लिए एक बार आरक्षित वार्ड को बदलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले की स्थिति को ही यथावत रखा जाएगा। जयेश गुरनानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत वार्ड आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया अपनाया जरूरी है। उनका तर्क था कि एक ही वार्ड को बार-बार आरक्षित रखने से वहां के दूसरे समुदायों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की भावना प्रभावित होती है। लेकिन, डिवीजन बेंच ने इसे सही नहीं मानते हुए सिंगल बेंच का फैसला पलट दिया।

इंदौर नगर पालिक निगम वार्ड आरक्षण

- वार्ड क्रमांक 1 - पुरुष, वार्ड
- क्रमांक 2 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 3 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 4 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 5 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 6 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 7 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 8 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 9 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 10 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 11 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 12 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 13 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 14 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 15 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 16 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 17 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 18 - अनुसूचित
- वार्ड क्रमांक 19 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 20 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 21 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 22 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 23 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 24 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 25 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 26 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 27 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 28 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 29 - सामान्य पुरुष

- वार्ड क्रमांक 30 - अनुसूचित महिला
- वार्ड क्रमांक 31 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 32 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 33 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 34 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 35 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 36 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 37 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 38 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 39 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 40 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 41 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 42 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 43 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 44 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 45 - अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड क्रमांक 46 - अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड क्रमांक 47 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 48 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 49 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 50 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 51 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 52 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 53 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 54 - अनुसूचित जाति पुरुष
- वार्ड क्रमांक 55 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 56 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 57 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 58 - पिछड़ा पुरुष

- वार्ड क्रमांक 59 - अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड क्रमांक 60 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 61 - अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड क्रमांक 62 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 63 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 64 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 65 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 66 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 67 - पिछड़ा महिला
- वार्ड क्रमांक 68 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 69 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 70 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 71 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 72 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 73 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 74 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 75 - अनुसूचित जनजाति
- वार्ड क्रमांक 76 - अनुसूचित जाति महिला
- वार्ड क्रमांक 77 - अनुसूचित जनजाति (महिला)
- वार्ड क्रमांक 78 - पिछड़ा पुरुष
- वार्ड क्रमांक 79 - अनुसूचित जनजाति (महिला)
- वार्ड क्रमांक 80 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 81 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 82 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 83 - सामान्य पुरुष
- वार्ड क्रमांक 84 - सामान्य महिला
- वार्ड क्रमांक 85 - सामान्य पुरुष

सोनम रघुवंशी को जेल में एक महीना पूरा जेल से आई हैरान करने वाली जानकारी

राजा की हत्या का किसी से जिक्र नहीं करती, परिवार से भी दूरी बना ली

इंदौर। शिलांग में हुए हनीमून मंडर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का पुलिस की कैद में एक महीना पूरा हो गया। पति राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम आरोपी है। शिलांग की जेल में सोनम रघुवंशी को एक महीना हो गया, लेकिन उसके तेवरों में कोई अंतर नहीं आया। पुलिस की कैद में रहकर भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसे अपने पति को मारने का भी कोई पछतावा भी नहीं है और न उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने आया। सोनम जेल के माहौल में भी ढल गई है। अन्य महिला कैदियों के साथ वह अच्छी तरह घुल-मिल गई और हर रोज सुबह ठीक समय पर उठती है और जेल मैनुअल का पालन करती है।

राजा की हत्या पर जिक्र नहीं

जानकारी के अनुसार, सोनम अपने पति की हत्या के बारे या निजी जीवन के बारे में किसी भी कैदी या जेल प्रशासन से बात नहीं करती है। वह जेल वार्डन के कार्यालय के पास रह रही है और दो विचाराधीन महिला कैदियों के साथ जगह साझा कर रही है। सोनम को अभी तक जेल के अंदर कोई काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन उसे सिलाई और कौशल विकास से जुड़े अन्य काम सिखाए जाएंगे।

उसने परिवार दूरी बनाई

विचाराधीन कैदी होने के नाते जेल नियमों के अनुसार, सोनम अपने परिवार के सदस्यों से मिल



सकती है। लेकिन, उसने किसी से मुलाकात या फोन नहीं किया है। जबकि, कुछ जानकारीयों में यह भी कहा गया कि उसे हर सप्ताह परिवार से बात करने की अनुमति है और उसने बात भी की। लेकिन, जेल सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। नौ दिन बाद दोनों 20 मई को मेघालय में अपने हनीमून के लिए रवाना हुए। इसके बाद खबर आई कि दोनों लापता हो गए। उनसे संपर्क न कर पाने पर उनके परिवारों ने पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद लापता का मामला हत्या में बदल गया, जब राजा का शव 2 जून को एक खाई में मिला। 7 जून की रात सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर बेहोशी की हालत में मिली। उसे इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम के प्रेमी राज सहित बाकी तीन हत्यारों को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

कटते पेड़, विभाग खामोश, हाईकोर्ट की रोक को ठेंगा, लकड़ी माफिया भी सक्रिय

फर्जी टीपी से आ रही अवैध लकड़ी, इंदौर की जीएनटी मार्केट अड्डा बना

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाई है। इसके बावजूद इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सरदारपुर, मनावर और चौरल जैसे क्षेत्रों में हरे-भरे पेड़ बेरहमी से काटे जा रहे हैं। वन विभाग की निष्क्रियता और अधिकारियों की मिलीभगत से वन माफिया बेखौफ हो चुके हैं। जानकारीयां बताती हैं कि ट्रकों और लोडिंग वाहनों में लकड़ी भरकर फर्जी ट्रांजिट परमिट (टीपी) के जरिए जीएनटी मार्केट तक पहुंचाई जा रही है। बालाघाट, गुना, राधोगढ़, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, सोनकच्छ, बालाघाट, शिवनी, और अशोक नगर जैसे जिलों के नाम पर बनाई जा रही इन फर्जी टीपी की आड़ में भारी मात्रा में नीम, आम, जामुन, महुआ और अर्जुन जैसे औषधीय वृक्षों की कटाई हो रही है। यह लकड़ी आरा मशीनों, चॉकलेट व ऑयल फैक्ट्रियों में खपाई जा रही है। जीएनटी मार्केट में बैठे दलालों की वन विभाग के डिट्टी रेंजर और कर्मचारियों से साठगांठ उजागर हो रही है। हर वाहन से 5,000 से 25,000 तक वसूली होती है, जो कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है। हाल में जब्त दो ट्रकों की खानापूर्ति जैसी कार्रवाई भी महज दिखावा साबित हुई। इस अवैध कटाई का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश अनियमित हो रही है और वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं।



कॉल सेंटर, टेलीपरफॉर्मंस सेंटरों पर धर्मांतरण के लिए स्लीपर सेल सक्रिय

लव जिह्वाद पीड़ित युवती ने पुलिस को इस रैकेट के बारे में बताया



इंदौर। एक ब्राह्मण युवती के साथ धर्मांतरण और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता ने सुल्तान रोशन नागोरी पर संगीन आरोप लगाए, जिसमें शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव, और अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग शामिल है। लसूडिया पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुल्तान के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और दुष्कर्म सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने कहा कि सुल्तान ने उसके ऊपर जादू-टोना भी करवाया ताकि वह उसके प्रभाव में आ जाए। युवती ने आरोप लगाया कि इंदौर में मुस्लिम हिंदू खासकर कोचिंग में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। लगभग 10 हजार हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के निशाने पर हैं। कॉल सेंटर और टेलिपरफॉर्मंस के कार्यस्थलों पर भी धर्मांतरण के लिए स्लीपर सेल सक्रिय हैं। युवती ने कहा कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों की टीम में रखा जाता है, जहां उन्हें बताया जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए बनाया है। इसके बाद उन्हें खाने में नशा

देकर शारीरिक शोषण किया जाता है। **नशा देकर शारीरिक शोषण:** पीड़िता ने बताया कि सुल्तान ने 2018 से उसके साथ शारीरिक शोषण शुरू कर दिया था। उसने धमकी दी कि अगर उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। होटल में शारीरिक संबंध के दौरान सुल्तान ने कई फोटो और वीडियो बनाए, जिससे दबाव बनाकर वह युवती को मुसलमान बनने के लिए मजबूर करता रहा। इस कारण पीड़िता 2019 में पंजाब चली गई और वहां नौकरी करने लगी। हालांकि, 2020 में सुल्तान की शादी के बाद मार्च 2025 में युवती इंदौर लौटी और टेली परफॉर्मंस में नौकरी शुरू की। 6 जून 2025 को सुल्तान ने फिर से उससे संपर्क किया और पुराने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए लसूडिया थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुल्तान को हिरासत में लिया। इस मामले ने शहर में सनसनी फैला दी। जांच में स्लीपर सेल्स और धर्मांतरण के कथित नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एंडिशल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

गणेश जी की आपत्तिजनक प्रतिमा बनाई, मूर्तिकारों के मुंह काले किए

बंगाली कलाकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

इंदौर। खजुराना इलाके में गणेश उत्सव की तैयारी में लगी एक मूर्तिकला टीम पर विवादित प्रतिमा बनाने का आरोप लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कलाकार ने भगवान गणेश की प्रतिमा को एक मॉडलिंग करती युवती को हाथ में उठाते हुए दर्शाया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध स्वरूप मूर्तिकार का मुंह काला कर उसे खजुराना थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। थाने में मूर्तिकारों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। कार्यकर्ता सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो यहां भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूप में मूर्तियां मिली। जिसके बाद मूर्तिकारों के मुंह पर काली स्याही पोती और फिर उन्हें थाने लेकर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा बनाने वाले बंगाली



कलाकारों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के जिला संयोजक लक्ष्मी रघुवंशी ने शिकायत में बताया कि मूर्तिकारों द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति गलत स्वरूप देकर मॉडलिंग करते भगवान गणेश द्वारा गोद में माडर्न युवती उठाकर स्वरूप में प्रस्तुत कर समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है। पूर्व में भी इन्होंने मूर्तिकारों ने माता जी को बुर्का पहनाते हुए गलत ढंग से प्रस्तुत किया था। पुलिस के मुताबिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज

हाई बोर्न न्यूट्रिशन

प्रतिष्ठान सील किया

इंदौर। सपना संगीता रोड टॉवर चौराहा स्थित हाई बोर्न न्यूट्रिशन एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड को बिना वैध खाद्य लाइसेंस संचालित करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में अवतार और न्यूट्रा वे ब्रांड के प्रोटीन पाउडर पाए गए, जिनके मालूने मौके पर ही परीक्षण हेतु संग्रहित किए गए। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए कि जब तक वैध खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक इसका संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है और इस तरह की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

कैफे संचालक के साथ मारपीट

इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र के गंगा देवी नगर स्थित नफफासी कैफे के संचालक के साथ मारपीट की गई। पुलिस को विकास ने बताया कि भाई साहिल के साथ अपने कैफे पर सामान रखवा रहा था। कैफे पर दो व्यक्ति नशे में आए और तेज आवाज में चिल्लाते लगे। मना किया तो मारपीट करने लगे। मामले में कुलदीप और करण कौशल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

जेवरात लेकर नौकर फरार

इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में अलमारी में रखी लोहे की तिजोरी लेकर नौकर फरार हो गया, उसमें जेवरात और नकदी रखी हुई थी। पुलिस को कुणाल अग्रवाल निवासी गड्डा गोल्फ लिंक कॉलोनी ने बताया कि 9 जुलाई को रात घर आया तो अलमारी खुली हुई थी। अलमारी में रखी लोहे की तिजोरी नहीं थी। अलमारी में रखा जेवरात, घड़ियां, नकदी आदि सामान नहीं था। नौकर सोनू कीर भी घर पर नहीं मिला। शंका है कि मेरा सोनू सामान चुरा कर ले गया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छावनी परिषद के बेढंगे काम

से जनता परेशान

महू। छावनी परिषद की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। परिषद द्वारा पहले पेवर ब्लॉक लगाना, फिर उन्हें उखाड़कर पास के मैदान में दोबारा लगाना। इस प्रक्रिया में लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह सब फर्जी बिलों और हेर-फेर के जरिए जनता के पैसे को खुली लूट है। हाट मैदान में हाल ही में लगाए गए पेवर ब्लॉक को बिना किसी वजह उखाड़ दिया गया और उन्हें पास के एक मैदान में फिर से बिछा दिया गया। जनता की ओर से कोई जनप्रतिनिधि सवाल नहीं उठा रहा है, जिससे परिषद मनमानी पर उतारू हो गई है। स्थानीय विधायक भी परिषद के सामने बेबस नजर आती हैं। कई बार उनके सुझावों को परिषद ने नजरअंदाज कर दिया। पूर्व पाषंदों की चुप्पी से जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। लोग अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

जयंती पर विशेष

सुरेन्द्र शर्मा

लेखिका शिक्षक हैं।



भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में चन्द्रशेखर आजाद का नाम सदा अग्रणी रहेगा। उनका जन्म 23 जुलाई, 1906 को ग्राम भावरा (जिला झाबुआ, वर्तमान में जिला आलीराजपुर मध्य प्रदेश) में हुआ था। उनके पूर्वज गाँव बदरका (जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश) के निवासी थे; पर अकाल के कारण इनके पिता श्री सीताराम तिवारी भावरा में आकर बस गये थे।

बचपन से ही चन्द्रशेखर का मन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सुलगता रहता था। किशोरावस्था में वे भागकर अपनी बुआ के पास बनारस आ गये और संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ने लगे। बनारस में ही वे पहली बार विदेशी सामान बेचने वाली एक दुकान के सामने धरना देते हुए पकड़े गये। थाने में हुई पूछताछमें उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतन्त्रता और घर का पता जेलखाना बताया। इस पर बौखलाकर थानेदार ने इन्हें 15 बेंतों की सजा दी। हर बेंत पर ये ‘भारत माता की जय’ बोलते थे। तब से ही इनका नाम ‘आजाद’ प्रचलित हो गया। आगे चलकर आजाद ने सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से देश को आजाद कराने वाले युवकों का एक दल बना लिया। भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, मन्मथनाथ गुप्त, शचीन्द्रनाथ सान्याल, जयदेव आदि उनके सहयोगी थे। आजाद तथा उनके सहयोगियों ने नौ अगस्त, 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल को काकोरी स्टेशन के पास रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। यह अंग्रेज शासन को खुली चुनौती थी, अतः सरकार नेक्रान्तिकारियोंको पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी।

पर आजाद को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वे वेष बदलकर क्रान्तिकारियों के संगठन में लगे रहे। ग्वालियर में रहकर इन्होंने गाड़ी चलाना और उसकी मरम्मत करना भी सीखा।

17 दिसम्बर, 1928 को इनकी प्रेरणा से ही भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने सांडर्स को यमलोक पहुँचा दिया। अब तो पुलिस बौखला गयी; पर क्रान्तिवीर अपनेकाम में लगे रहे।कुछ समय बाद क्रान्तिकारियों ने लाहौर विधानभवन में बम फेंका। यद्यपि उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। बम फेंककर भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके वीरतापूर्ण वक्तव्यों से जनता में क्रान्तिकारियों के प्रति फैलाये जा रहे भ्रम दूर हुए। दूसरी ओर अनेक क्रान्तिकारी पकड़े भी गये। उनमें से कुछ पुलिस के अत्याचार न सह पाये और मुखबिरी कर बैठे। इससे क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर

मन का मौसम

ललिता जोशी

लेखक स्वतंत्र प्रकाश हैं।

सावन के आते ही बारिश से प्यासी और तपती धरती का तन -मन प्रसन्न हो जाते हैं। धरती का ताप शांत होता है और पेड़ -पौधों को गर्मी से निजात मिल जाती है। बरसात आते ही सावन का इंतज़ार शुरू हो जाता है। सावन में तन और मन दोनों पर खुमार चढ़ता है प्रेम का। आसमान पर उमड़ते -घुमड़ते बादल और उनसे बरसता पानी कहना ही क्या ऐसे मौसम का। थोड़ा रोमानी थोड़ा मस्ती। अपने यहाँ बरसात और सावन पर अनेक लोकगीत और कवितायें और फिल्मी गीत हैं। बरसात और सावन एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए इस मौसम का किसान को अपनी फसल के लिए,प्रेमियों को मुलाकातों के लिए,प्रकृति को अपने श्रृंगार के लिए और बादलों को फटने के लिए, तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए इंतज़ार होता। देवों के देव महादेव के आशीष के लिए सावन में विशेष पूजा-अर्चना और काँवड़ यात्रा भी की जाती है। सावन महिना है कर्म, अध्यात्म और रोमांस का।

सावन पर एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत है ‘ तेरी दो टकियों की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए’ जिस दौर में ये गीत लिखा गया होगा तो उस समय नौकरी पर सावन भारी पड़ता होगा लेकिन आज जिसे पे-पैकेज लाखों और करोड़ों में मिलता है वो रोज सावन की मस्तिष्क ले सकते हैं। बेचारा मध्यमवर्गीय व्यक्ति जो रोज अपने और अपने परिवार के लिए कमाने निकलता है तो उसे सड़कों पर जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम से जूझता हुआ आदमी ऑफिस पहुँचे और फिर वापस घर आए तो उसे कहीं से सावन की खुमारी आणगी। सावन में रोज ऐसी समस्याओं से झूझते आदमी को सावन रोमानी लगेगा या बेमानी। तब तो ये लगता है कि तेल

पुण्यतिथि पर विशेष

सुसंस्कृति परिहार

लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।



सैयद हैदर रजा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार तो थे ही, कविता के प्रति उनका अटूट राग है उनके मानस में एक संस्कारवान कवि मौजूद रहा वह चित्रों में उतर आता था उनके चित्र एक अलग तरह की कविता के मानिंद हैं। कविता की किताब उनके हाथ में जब आती थी तो वे उसे आधीपांत पढ़ते थे। उनकी डायरी में कबीर, मीर, गालिल, निराला, महादेवी, शेरी भोपाली के साथ-साथ केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेई और गिरधर राठी से लेकर पवन करण तक की कविताएं मौजूद रहीं।

रजा साहब अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कहते थे कि- ‘सिर्फ विचार से काम नहीं बनता उसके लिए साधना और एकाग्रता बहुत जरूरी है रचना से तादात्म्य भी जरूरी है लेकिन कभी-कभी तनाव का ऐसा मुकाम भी आता है, जब विचार प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और सहज बुद्धि हावी हो जाती है। तब मैं खुद से पूछना भी छोड़ देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ? बस विचार आते जाते हैं मैं उन्हें कैनवास पर उतारता जाता हूँ।’ वस्तुतः उनकी मान्यता है कि कविता में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कलाकर्म समय मांगता है मानवीय अनुभव सिर्फ आंख से देखना नहीं बल्कि यह महसूस करना भी है जो आंख की पुतली से परे भी दिखाई देता है।जैसे हम उष्णता महसूस कर सकते हैं, आंधी का झोंका झेल सकते हैं, ताजा हवा की गंध, जंगल का संगीत, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। नंगी आंखों से देखने की क्षमता से आगे बढ़कर हम तमाम अनुभवों को मन के भीतर तक महसूस कर सकते हैं वही संपूर्ण अनुभूति

वीथिका

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चन्द्रशेखर ‘आज़ाद’

बचपन से ही चन्द्रशेखर का मन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सुलगता रहता था ।किशोरावस्था में वे भागकर अपनी बुआ के पास बनारस आ गये और संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ने लगे ।

बनारस में ही वे पहली बार विदेशी सामान बेचने वाली एक दुकान के सामने धरना देते हुए पकड़े गये ।थाने में हुई पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का

पता जेलखाना बताया ।इस पर बौखलाकर थानेदार ने इन्हें 15 बेंतों की सजा दी ।हर बेंत पर ये ‘भारत माता की जय’ बोलते थे ।तब से ही इनका नाम ‘आजाद’ प्रचलित हो गया ।आगे

चलकर आजाद ने सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से देश को आजाद कराने वाले युवकों का एक दल बना लिया ।भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, मन्मथनाथ गुप्त,

शचीन्द्रनाथ सान्याल, जयदेव आदि उनके सहयोगी थे ।आजाद तथा उनके सहयोगियों ने नौ अगस्त, 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली रेल को काकोरी स्टेशन के पास रोककर

सरकारी खजाना लूट लिया ।यह अंग्रेज शासन को खुली चुनौती थी, अतः सरकार ने क्रान्तिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी ।

पड़ गया। केन्द्रीय असेंबली में बम चन्द्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली की केन्द्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस काण्ड के फलस्वरूप क्रान्तिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केन्द्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार-मंच बनाना चाहते थे। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम-परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गयी थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फाँसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधीजी के पास भेजा जहाँ से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था। आजाद ने अपने बलबूते पर झाँसी और कानपुर में अपने अंडे बना लिये थे। झाँसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर, भगवानदास माहौर तथा विश्वनाथ वैशम्पायन थे जबकि कानपुर में पण्डित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे

आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़े चन्द्रशेखर आजाद ॥ क्या आप जानते है अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद अपनी इस एकमात्र तस्वीर को नष्ट करना चाहते थे।चंद्रशेखर आजाद की आजाद की एक तस्वीर हम सबने देखी है। जनेऊ पहले हुए और मूर्छों पर ताव देते हुए इस तस्वीर का किस्सा बड़ा दिलचस्प है काकोरी एक्शन के बाद जब आजाद गुप्त प्रवास पर थे, तो वो झाँसी में अपने दोस्त मास्टर रुद्रनारायण के घर पर भी रुक़ थे। रुद्रनारायण जी को फोटोग्राफी का शौक था। उन्होंने ही ज़िद करके आजाद की ये फोटो खींची थी।

आजाद को हर वक्त जासूसी का खतरा रहता था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी फोटो खींची जाए। उस वक्त तक उनकी एक भी फोटो अंग्रेज़ों के पास नहीं थी।

मास्टर रुद्रनारायण ने कहा कि उन्हें एक फ़ोटो इसलिए खिंचवा लेनी चाहिए कि आने वाले वक्त में लोग समझ सकें कि



भारत का ये महान क्रांतिकारी उन्ही की तरह आम शक्ल सूरत का था मगर उसकी भावना और साहस ने उसे खास बना दिया। मास्टर रुद्रनारायण ने भरोसा दिया कि ये फोटो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इस फोटो के खिंचने के कुछदिन बाद ही आजाद को लग गया कि उनसे गलती हुई है उन्होंने अपने दोस्त विश्वनाथ वैशम्पायन को रुद्रनारायण के पास भेजा कि वो तस्वीर नष्ट की जाए मगर रुद्रनारायण ने वैशम्पायन को भरोसा दिया कि फोटो बहुत अहम है, आजाद के जीते जी वो इसे सार्वजनिक कभी नहीं करेगा। वो इसके निगेटिव को दीवार में चुनवा दे रहे हैं, इसके सब प्रिंट नष्ट किये दे रहे हैं। आजाद को बता दिया जाए कि ये फोटो नष्ट कर दी गयी है. वैशम्पायन ने ऐसा ही किया।

आजाद जब बलिदान हो गए तब यह फोटो मास्टर रुद्रनारायण ने दीवार से निगेटिव निकलवा कर बनवाई और इस तरह देश के सामने आई उस महान क्रांतिकारी की एकमात्र जीवंत छवि जो आज तक देश के तमाम वासियों के मन में बसी है। ‘भारत की फ़िज़ाओं को सदा याद रहूँगा आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा !’

वह 27 फरवरी, 1931 का दिन था। पुलिस को किसी मुखबिर से समाचार मिला कि आज प्रयाग के अल्फ़्रेंड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद किसी से मिलने वाले हैं। पुलिस ने समय गँवाये बिना पार्क को घेर लिया। आजाद एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही

उपफ ये सावन, हरा भी मन भरमाया भी

आसमान पर उमड़ते –घुमड़ते बादल और उनसे बरसता पानी कहना ही क्या ऐसे मौसम का। थोड़ा रोमानी थोड़ा मस्ती । अपने यहाँ बरसात और सावन पर अनेक लोकगीत और

कवितायें और फिल्मी गीत हैं। बरसात और सावन एक सिक्के के दो पहलू हैं । इसीलिए इस मौसम का किसान को अपनी फसल के लिए,प्रेमियों को मुलाकातों के लिए,प्रकृति को

अपने श्रृंगार के लिए और सड़कों,पुलों और फ़लाइओवरों को ढहने के लिए और बादलों को फटने के लिए, तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा के लिए इंतज़ार होता। देवों के देव महादेव के

आशीष के लिए सावन में विशेष पूजा-अर्चना और काँवड़ यात्रा भी की जाती है। सावन महिना है कर्म, अध्यात्म और रोमांस का।

लेने जाए ये सावन । कोई जमाना था जब सावन में बरसात का मजा आता था । पहली बरसात में नहाने का मजा अलग ही था । जेठ-माह की गर्मी से तप्त शरीर को सावन की बरसात और उससे मौसम में आए बदलाव से तन और मन दोनों को ही प्रफुल्लित कर जाते हैं। किसी ने प्रेमियों के लिए सही ही कहा है

‘सर्मा हो फागुन का या बारिश हो सावन की मोहब्बत सुलगती रहती है इन दिनों’ ‘सावन का ये मौसम कुछ याद दिलाता है किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है’ ये तो थी प्रेमियों के लिए कुछ पंक्तियां। लेकिन बेचारा प्रेमी टूटी और पानी भरी सड़कों को पार कर कैसे आए लेकिन प्रेमी जी को एक लड़की भीगी -भागी सी अच्छी लगती है। जब मिलन में इतनी कठिनाइयाँ हो तो मिलन का उत्साह काफ़ूर हो जाता है। अगर घरों में पानी भर जाए तो कैसा सावन । वो तो घर से बेघर हो जाते हैं तो सावन ही दो टकियों का लगने लगता है। अरे भाई ऐसे में क्या और कैसा सावन ? मन के हिलोरे मन में ही रह जाते हैं।

सावन में पहाड़ों में शिवजी के दर्शनों के लिए यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जगह जगह रास्ते टूट जाते हैं और यात्रा ठप हो जाती है। रुक- रुक कर ये यात्राएं चलती हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं पहाड़ का टूटना तो कहीं बादलों का फटना । पुलों का गिरना, सड़क का अस्तित्व खतरे



में। शिवभक्ति के इस मौसम में जैसे शिव साक्षात अपना तांडव करते महसूस होते हैं। वैसे तो हर मौसम की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती हैं। लेकिन जब -जब अपना सावन आया झूम के जो आम आदमी को जाए घूमा के । ऐसे ही पहले बच्चे बारिश के पानी में कागज की कश्तियाँ बनाकर बहाते थे लेकिन अब ये दृश्य देखने को नसीब ही नहीं होते ।

अब तो अभिभावकों को बच्चों को ऐसे मौसम में बाहर भेजने में ही डर लगता है की कहीं बेचारे खुले खड्डों,मेनहोल में न गिर जाएँ । न जाने कितने बच्चे इन हादसों के शिकार बन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सिविक एजेंसियों की लापरवाही से जान पर आ बनती है। ये है बदलते जमाने का बदलता सावन।यहाँ एक गीत याद आ रहा है - जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका को

कह रहा है तुम्हें गीतों में ढलूँगा, सावन को आने दो....

जो अब आफत लगता है। इस मौसम में हवा चलनी बंद हो जाए तो सांस लेना ही दुभर हो जाता है। इस मौसम का डॉक्टरों को भी इंतज़ार रहता क्योंकि इसमें मौसमी बुखार और डेंगू मलेरिया अपने उच्च उठान पर होती है तो इन डॉक्टरों की कमाई अपने चरम पर होती है। बेचारा मरीज त्रस्त लेकिन डॉक्टर मस्त ।

इस मौसम में पेड़ों की शामत आई रहती बारिश और हवा एक साथ होने लगे तो बेचारे धराशायी हो जाते हैं और रास्ते बंद। इतना ही जब सड़कों पर पानी भरता है तो गाड़ी वाले पैदल चलने वालों को पानी सराबोर करके चलते हैं। जैसे कि गाड़ी वाला मुंह चिढ़ाकर कह रहा हो मेरी मर्जी । सावन की बारिश जब अपने चरम पर होती है तो सब कुछ ठहर जाता है । ये है सावन की शक्ति लेकिन इस पर भारी पड़ती है भक्ति । शिव भक्त सावन की रात से निर्भय हो अपनी भक्ति से शिवजी को पाने के लिए यात्राएं करते हैं। पूरा सावन शिव को समर्पित है। दूसरी ओर महिलायें इस मौसम में तीज का आनंद लेती हैं। महिलाओं को मायके से तीज पर उपहार मिलते हैं। सावन और हरा रंग का एक अटूट बंधन है। हरी चुड़ियाँ, हरी साड़ी सब सावन को और हरीतिमा प्रदान करती हैं । वैसे सावन में प्रकृति अपने पर हरियाली की चादर ओढ़ सभी को सुकून प्रदान करती है । एक कबखत भी ‘सावन के अंधे को सब हरा ही नज़र आता है।’ उपफ़ ये सावन

हैदर रजा: कविता और रंगों की कदमताल

रजा साहब अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कहते थे कि- ‘ सिर्फ विचार से काम नहीं बनता उसके लिए साधना और एकाग्रता बहुत जरूरी है रचना से तादात्म्य भी जरूरी

है लेकिन कभी-कभी तनाव का ऐसा मुकाम भी आता है, जब विचार प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और सहज बुद्धि हावी हो जाती है। तब मैं खुद से पूछना भी छोड़ देता हूँ

कि मैं क्या कर रहा हूँ? बस विचार आते जाते हैं मैं उन्हें कैनवास पर उतारता जाता हूँ।’ वस्तुतः उनकी मान्यता है कि कविता में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कलाकर्म

समय मांगता है मानवीय अनुभव सिर्फ आंख से देखना नहीं बल्कि यह महसूस करना भी है जो आंख की पुतली से परे भी दिखाई देता है। जैसे हम उष्णता महसूस कर

सकते हैं, आंधी का झोंका झेल सकते हैं, ताजा हवा की गंध, जंगल का संगीत, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। नंगी आंखों से देखने की क्षमता से आगे बढ़कर

हम तमाम अनुभवों को मन के भीतर तक महसूस कर सकते हैं वही संपूर्ण अनुभूति है।



है। किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए और चित्रकार एवं कलाकार की क्षमता सामान्य से थोड़ी अधिक होती है। मनुष्य और सकल ब्रह्मांड के आंतरिक संबंध को मानते हुए रज़ा ने कहा था कि- ‘बड़ी बात है इसे चित्र कविता वाली कला में लाना। चित्रकार जीवन या कलाकृतियों के आसपास की बात कर पाता है स्वाद, सुगंध, पीड़ा, आनंद समझाएँ नहीं जाते ना इसका तो अनुभव ही किया जाता है। वे मानते हैं आंख बंद कर भी चित्र बनाए जा सकते हैं चित्र आंखों से नहीं मन

से, हृदय से, तमाम सोचने की शक्ति से भी बनने चाहिए एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम को समझते हैं तब जाकर प्रेम के ऊपर एक अच्छी कविता लिख पाते हैं वही बात चित्रों के लिए है।’ वे कहते हैं मानवीय जीवन के उच्चतर पक्ष को प्रमाणित चित्रों में प्रतिबिंबित किया जा सकता है अपने चित्रों के बारे में उनका कहना है मैंने भारतीय परंपरा के उन नौ रसों की दिशा में अपनी चित्र कृतियों का विकास किया है । अशोक बाजपेई जैसे वरिष्ठ कवि

और रजा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। बाजपेई रजा के चित्रों पर कविता लिखते हैं तो रजा वाजपेई की कविता का चित्र पेश करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ बरसों तक कदमताल करते रहे हैं। रजा की एक कृति पर उनकी कविता है-

‘आओ जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास जैसे जल मिलता है जल में जैसे रोशनी घुलती है रोशनी से।’

यहां रजा के रंग को अशोक शब्द की तरह अपने विन्यास के लिए विकल्प होते दिखाई देते हैं। कवि ध्रुव शुक्ल को रजा की ‘सूर्य नमस्कार’ कृति देखकर केदारनाथ सिंह याद आते हैं- आप विश्वास करें मैं कविता नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आग की ओर इशारा कर रहा हूँ ध्रुव शुक्ल ने भी रजा के चित्रों पर कई कविताएं लिखी हैं उनका मानना है कि रजा के चित्रों पर जब मैंने

कविताएं लिखीं तो मुझे उनमें भी अलौकिक मां नजर आई जो कि स्वयं अपने ही आल्हाद की गोद में बैठी है। वे लिखते हैं -

उनके चित्रों में दिखती व्याकुल पुरातन मां शिशु के साथ कभी उन्हें रजा के चित्र रंगों की अक्षत से भरी पूजा की थाली जैसे लगते हैं वे लिखते हैं - ‘पुष्पों की पंखुड़ियों से भरी पूजा की थाली जैसे ये चित्र रंगों के उद्गम पर खड़े प्रार्थना मग्न बेहद के मैदान में बिखर रही है उनके हाथों से छिटकी रंगों की अक्षत’ निश्चित ही, रजा चित्रकला एवं काव्य के समन्वयक हैं उनका वजुद कविता से सराबोर है। यही वजह है कि उनके चित्र कवियों की कविताओं में भी उभरे हैं चित्र और कविता की कदमताल ही रजा की अपनी एक अलग पहचान है।

राइट क्लिक



अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।

संपर्क:- 9893699939
ajayboki1@gmail.com

बिहार विधानसभा चुनावों पर कितना असर डालेगा एसआईआर?

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव यूं तो अक्टूबर अथवा नवंबर में होने हैं, लेकिन इसके पहले राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जमकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष इसे चुनाव आयोग के माध्यम से सत्तारूढ़ भाजपा का 'खेला' मान रहा है, जो भाजपा और एनडीए का कहना है कि यह एक 'सामान्य प्रक्रिया' है। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर 'मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया' है। क्योंकि राज्य में 2003 के बाद से मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन इस एसआईआर से शक्ति राजद नेता और विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मोदी सरकार द्वावा बिहार में 'वोटबंदी' की संज्ञा दी है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी 'वोटों की चोरी की साजिश करार दे रहे हैं। एआईएमआईएम ने तो एसआईआर को 'बैक डोर से एनआरसी की वापसी' बता दिया है। विपक्ष का सवाल है कि वोटर लिस्ट का 'शुद्धिकरण' अभी ही क्यों? यह काम चुनाव बाद भी किया जा सकता है। विपक्ष को आशंका है कि एसआईआर के बहाने उसके समर्थक वोटों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों और दलितों की हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एसआईआर से राज्य में सभी की नागरिकता की विश्वसनीयता सदेह के घेरे में आ गई है।

इस बीच चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। उसका दावा है कि राज्य में एसआईआर के 95 फीसदी फार्म जमा हो चुके हैं। राज्य में 43.92 लाख मतदाता या उनके पतों पर नहीं मिले या फिर उनके दस्तावेज अधूरे हैं। आयोग ने इन वोटरों को चार अलग-अलग श्रेणी में रखा है। इनकी सूची 12 राजनीतिक पार्टियों को दे दी गई है। 11 हजार 484 वोटर ऐसे भी हैं, जिनका कहीं कोई पता नहीं चला। जिन्हें आयोग संदिग्ध मान रहा है, उन वोटरों की संख्या राज्य के कुल वोटरों का लगभग 5 फीसदी है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हालांकि इनके नाम सूची से बीएलओ द्वारा फिर से जांच के बाद ही हटेंगे।

उधर एसआईआर से परेशान ने विपक्ष ने जहां इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि इस मुद्दे पर उसे खास राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को उसका काम करने नहीं रोकेगा। हालांकि कोर्ट ने न्याय हितों में सुझाव दिया कि आयोग मतदाता की पुष्टि

के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर भी विचार करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं। इनमें एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज के अलावा आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी याचिका थी। इसके पूर्व 11 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच मतदाताओं द्वारा एसआईआर फॉर्म जमा करने के मामले में धांधलियों की शिकायतें भी आईं और ऐसा एक मामला उजागर करने पर एक पत्रकार के खिलाफ मामला भी कराया गया।

उधर राजनीतिक हंगामे के बाद भी चुनाव आयोग अपना काम किए जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम पाए गए, जिन्हें 1 अगस्त के बाद नागरिकता जांच के बाद हटाया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि इस मुद्दे को किसी तरह विधानसभा चुनाव तक खींचा जाए। संभव है कि यदि एसआईआर में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे तो यह जनक्रोश का कारण बन सकता है, हालांकि कितना बनेगा, यह अभी कहना कठिन है। मतदाता सूची अद्यतन हो, उससे से अपात्रों के नाम हटें, इस पर किसी को शायद ही आपत्ति हो। लेकिन नाम जुड़वाने के लिए आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है और इसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उस पर बहुतों को आपत्ति है। कहा जा रहा है कि जो डब्युमेंट मांगे जा रहे हैं, वो कई लोगों के पास नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को अलग श्रेणी में रखकर उनका समाधान करने की बात कही है, लेकिन लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि एसआईआर ' के कड़े दस्तावेजीकरण नियम (जैसे 2003 की मतदाता सूची या माता-पिता के जन्म प्रमाण) के चलते गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इस अभियान के शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा था, 'लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाता अधिकारों का चौराहरण हो रहा है। फर्जी फॉर्म और असंवैधानिक कार्यवाहनी लोकतंत्र के लिए घातक है।' इस मुद्दे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पटना रेली में सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का 'चुनाव चोरी' विंग बन गया है? विपक्ष का दावा है कि बिहार के 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण

और गरीब आबादी के लिए आयोग द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेजों को जुटाना मुश्किल है, जिससे उनका वोटिंग अधिकार छिन सकता है।

उधर टीएमसी नेता महुआ मोहना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसआईआर को 'लोकतंत्र पर हमला' बताते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया बीजेपी के इशारे पर शुरू की गई ताकि गरीब और प्रवासी मतदाताओं को वोट से वंचित किया जाए। इसका कारण यह भी है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी लागू होने वाला है, जहां टीएमसी की सरकार है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना था कि वह किसी की धारणाओं का जवाब नहीं दे सकता। वह अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। यह आशंका गलत है कि उसका उद्देश्य बड़ी संख्या में मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने का है। आयोग के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट बनाने और उसमें सुधार का जिम्मा देता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट,1950 की धारा 21(3) उसे मतदाता लिस्ट में सुधार के लिए विशेष सचन अभियान चलाने की शक्ति देती है। इस प्रक्रिया से जुड़े नियम बनाने का अधिकार भी कानून आयोग को देता है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह मोबाइल फोन के जरिए मैसेज भेजने के अलावा घर-घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहा है। अगर किसी का नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आ पाया, तब भी उसे पूरा मौका दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी इस तरह का अभियान चलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा।

दरअसल चुनाव आयोग हर बड़े चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करता है ताकि फर्जी वोटरों के नाम हटाए जा सकें और नए, योग्य मतदाताओं को जोड़ा जा सके। बिहार में इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं की सूची की गहन जांच हो रही है। इसके लिए हर वोटर से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के जन्म से जुड़े कागजात, या 1987 से पहले के राशन कार्ड और जमीन के दस्तावेज।

जबकि विपक्ष का तर्क है कि चूंकि बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। इतने कम वक्त में 8 करोड़ लोगों के दस्तावेज जमा करवाना और उनकी जांच करना मुश्किल लगता है। ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए है। विरोधी पार्टियों को डर है कि इस प्रक्रिया से राज्य में 2 से 4

करोड़ वोटरों के नाम हट सकते हैं, खासकर दलित, ओबीसी, और अल्पसंख्यक समुदायों के।

एनडीए नेता इस प्रक्रिया को सही ठहरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीवन राम मांडी ने कहा कि फर्जी वोटरों को हटाने से डर केवल 'गलत' लोगों को है। उनका दावा है कि कुछ इलाकों में 25-30 हजार फर्जी वोटर हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को साफ-सुथरी मतदाता सूची से परेशानी है, क्योंकि उनके 'फर्जी वोटर' हट जाएंगे। बहरहाल, इस घमासान का पार्ट टू तब शुरू होगा, जब पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी होगी। अगर इसमें बड़ी संख्या में किसी खास वर्ग या समुदाय के नाम कटे तो नया राजनीतिक घमासान शुरू होगा। उस स्थिति में राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए और खासकर भाजपा को भी परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो विपक्षी का एसआईआर को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचने की बात है। इसके अलावा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। विपक्ष के इस वार को बेअसर करने के लिए एनडीए और नीतीश सरकार ने रेवड़ी कल्चर का दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा दांव तो प्रदेश में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरियां व रोजगार देने का है। बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़ चार लाख बताई जाती है।

राज्य में 4 लाख 72 हजार 976 पद खाली बताए जाते हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। यानी सभी पद भर चुके हैं। ऐसे में नए लोगों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचने की बात है। इसके अलावा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। विपक्ष के इस वार को बेअसर करने के लिए एनडीए और नीतीश सरकार ने रेवड़ी कल्चर का दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा दांव तो प्रदेश में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरियां व रोजगार देने का है। बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़ चार लाख बताई जाती है।

नव संकल्प शिविर

कांग्रेस अतीत पर विचार नहीं कर रही, भविष्य की ठोस रूपरेखा भी बना रही

शिविर के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये नवयुग का आरंभ

धारा। जिले के मांडव में चल रहे मध्यप्रदेश कांग्रेस के दो दिवसीय नव संकल्प शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। इससे

पहले सभी विधायकों और नेताओं ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। पूरे शिविर को लेकर मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि यह दो दिन किसी समापन का नहीं, बल्कि नवयुग के संकल्प का आरंभ हैं। नव संकल्प शिविर ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कांग्रेस केवल अतीत पर विचार नहीं कर रही, बल्कि भविष्य की ठोस रूपरेखा बना रही है। कांग्रेस ने मांडव की ऐतिहासिक धरती से मध्यप्रदेश की तकदीर बदलने का संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। किसानों को आय का अधिकार। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करना। युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप के लिए समर्थन। दलितों-आदिवासियों और वंचित वर्गों को उनका अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने लड़ने और जीतने का मन बनाया है। इस शिविर से विधायकों में नई ऊर्जा और स्पष्ट रणनीति उभरी है। यह कांग्रेस के वैचारिक नवचिंतन की शुरुआत है, जिसे प्रदेशभर में संवाद और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह संकल्प एक विचार था, जिसे जमीन पर उतारने की ताकत हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निरंतर समर्थन और आशीर्वाद से मिली। सर्वश्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और हरीश चौधरी जी का मार्गदर्शन और जीतू पटवारी जी का साथ हमारे लिए संबल बना। कांग्रेस के सभी विधायक शिविर में पूरी निष्ठा और गंभीरता से शामिल हुए। यह कोई साधारण बैठक नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साझा संकल्प था।

जनहित के मुद्दों पर समूह चर्चा

कांग्रेस विधायकों को 10-10 विधायकों के 6 समूहों में बांटा

गया और हर समूह ने प्रमुख जनहित मुद्दों पर गहन मंथन किया। इसके प्रमुख विषय थे जातिगत जनगणना, 27 प्रतिशत ओबीसी

आरक्षण, वन अधिकार कानून, पेसा एक्ट और जनजातीय अधिकार के अलावा संगठन सुजन अभियान और कांग्रेस का जमीनी विस्तार भी रहा। एसएनजी, एनजीओ, सहकारी संस्थाएँ और समाजसेवी नेटवर्क पर भी बातचीत हुई।

कांग्रेस की एकता से भाजपा में खलबली

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भाजपा पर सीधा निशाना: नव संकल्प शिविर की सफलता से भाजपा में स्पष्ट घबराहट है। हमने मांडव में नवसंकल्प लिया है, भाजपा की तरह पंचमढ़ी में हनीमून नहीं मनाया। भाजपा डर रही है कि आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस उनके भ्रष्टाचार, विफल योजनाओं

और जनविरोधी फैसलों की परतें खोलेगी और हम यह जरूर करेंगे। लेकिन, नव संकल्प शिविर का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा और दीर्घकालिक है। यह शिविर एक वैचारिक और सांगठनिक तैयारी है, जो भाजपा की जड़ें प्रदेश में हिला देने की क्षमता रखता है।

कांग्रेस का रणनीतिक दस्तावेज तैयार

नव संकल्प शिविर के दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस ने एक आंतरिक और रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया है, जो आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक रणनीतियों, जनसपर्क अभियानों और सांगठनिक विस्तार का आधार बनेगा।

भाजपा के राज की खासियां

प्रदेश में भाजपा सरकार के कमीशन और घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। आज किसान परेशान हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है एससी-एसटी पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करने की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। किसान, मजदूर, युवा, महिला दलित और आदिवासी सहित हर शोषित और वंचित की हक और अधिकार की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी।

सुंदर-स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का उपहार है पौधरोपण : मुख्यमंत्री

भोपाल के मानव संग्रहालय में रोपे गए 4 हजार पौधे, हमसे जहां कहीं गलतियां हुईं, वहां दोबारा पौधारोपण की जरूरत



भोपाल (नप्र)। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 4 हजार पौधे रोपे गए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक अशोक पांडे, सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, विधायक भगवानदास सबनानी, मेयर मालती राय और भोजपाल मित्र संस्था के कार्यकर्ता मौजूद थे।

मप्र में सबसे ज्यादा वन संपदा- सीएम ने

कहा- आज यहां (मानव संग्रहालय) चार हजार पौधे रोपे जा रहे हैं। भोपाल नगर में मिलाकर 5100 पौधे लगाने का संकल्प है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी का जीवन वृक्ष और बाकी जनजीवन से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परस्पर एक दूसरे पर अवलंबन ये हमारे लिए जीवन प्रदान करता है। खासकर मप्र तो और भाग्यशाली है। पूरे देश के बाकी राज्यों की तुलना में यदि सर्वाधिक वन संपदा कहीं हैं तो मप्र में हैं।

लीला साहू बोलीं- सांसद जी हेलिकॉप्टर भेजिए, हमें उठवा लीजिए

कहा- प्रेग्नेंसी का नौवां महीना है, सड़क नहीं बनी, आपने उठवाने की बात की थी

सीधी (नप्र)। सीधी जिले की गर्भवती सोशल मीडिया इम्प्लूएंसर लीला साहू का एक और वीडियो सामने आया है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के ग्राम खड्डी खुर्द की लीला साहू ने सांसद डॉ. राजेश मिश्रा से हेलिकॉप्टर भेजने की मांग की है।

लीला गर्भावस्था के नौवें महीने में हैं। उनके गांव तक अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए उन्होंने सांसद से कहा कि आपने वादा किया था, जरूरत पड़ने पर हेलिकॉप्टर भेजेंगे, अब वह समय आ गया है।

इससे पहले लीला ने एक वीडियो में नेताओं से सवाल किया था कि उन्होंने 29 सीटें दिलाई हैं, फिर भी उनके गांव की सड़क क्यों नहीं बन रही? विधायक प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि एक गर्भवती महिला को सड़क के लिए गुहार लगानी पड़े, यह प्रशासन के लिए शर्म की बात है।

लीला अपने गांव की सड़क के लिए पिछले साल से संघर्ष कर रही हैं। उनके गांव में सड़क नहीं होने से दो महिलाओं की जान जा चुकी है। इनमें एक उनकी भाभी ममता थीं। दूसरी महिला सीमा थीं।

पिछले साल जुलाई में की

थी सड़क की मांग

लीला साहू ने जुलाई 2024 में अपने गांव खड्डी खुर्द के बगेया टोला से गजरी को जोड़ने वाली 10 किमी लंबी कच्ची सड़क की खस्ता हालत को उजागर किया था। इसी को लेकर उन्होंने पहला वीडियो डाला था।

इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और सीधी के सांसद राजेश मिश्रा को टैग करते हुए सड़क निर्माण की मांग की थी। लीला ने बताया कि बारिश में यह सड़क कीचड़ और गड्ढों से भर जाती है, जिसके कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहनों का आना-जाना असंभव हो जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है।

गर्भवती महिलाओं का साथ दूसरा वीडियो डाला था- इसके बाद लीला साहू गर्भवती हुईं तो दूसरा वीडियो भी बनाया। उन्होंने कहा- खराब सड़क के कारण गर्भवतियों को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके गांव में छह अन्य गर्भवती महिलाएं भी थीं।

भोपाल (नप्र)। भोपाल में अब तक

15.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो अब तक की औसत बारिश 13 इंच से पौने तीन इंच ज्यादा है। बावजूद अब तक डैम या तालाब नहीं छलके हैं। बड़ा तालाब 6.6 फीट है। कलियासोत डैम को पूरा भरने में साढ़े 10 फीट पानी की जरूरत है। कोलार और केरवा डैम भी नहीं छलके हैं।

पिछले साल जुलाई में ही 3 डैम-कोलार, भद्रभदा और कलियासोत डैम ओवरफ्लो हो गए थे। वहीं, बड़ा तालाब भी लबालबा भर गया था। मौसम विभाग के अनुसार, इस बार भोपाल में बारिश के स्ट्रॉंग सिस्टम की एक्टिविटी कम रही है। इस वजह से तालाब और डैम में ज्यादा पानी नहीं बढ़ा, लेकिन अगले सप्ताह से फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। जिससे अगस्त के पहले सप्ताह तक अच्छा पानी आ सकता है।

सीहोर में भी तेज बारिश की दरकार

सीहोर में तेज बारिश होने से कोलांस नदी उफान पर आणी, जिससे बड़ा तालाब में पानी और बढ़ेगा। यहां भी तेज बारिश की दरकार है। सीहोर में अब तक औसत साढ़े 17 इंच पानी गिर चुका है।



जलस्रोतों में इतना पानी

बड़ा तालाब- इसकी जलभराव क्षमता 1666.80 फीट है। अभी इसमें 1660.20 फीट पानी है। इसे पूरा भरने में अभी 6.60 फीट पानी की और जरूरत है। पिछली बार बड़ा तालाब जुलाई में ही भर गया था, लेकिन इस बार अभी भी खाली है। बड़ा तालाब पूरा भरने के बाद भद्रभदा डैम के गेट खुलते हैं। इस बार कैचमेंट एरिया में कम बारिश हुई है। जिससे कोलांस नदी लबालबा होकर नहीं कहीं।

कोलार डैम- इसका वॉटर लेवल 1516.40 फीट है। अभी इसमें 1490.74 फीट पानी जमा है। इस हिसाब से यह काफी खाली है। कोलार डैम से ही भोपाल शहर के 40 प्रतिशत हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती है। पिछली बार जुलाई में इसके गेट खोलने पड़े थे। केरवा डैम- कुल 1673 फीट वाले केरवा डैम में अब तक 1653.08 फीट पानी आ चुका है। बारिश नहीं होने से आवक फिलहाल थमी हुई है।

कलियासोत डैम- डैम का वॉटर लेवल 1648.62 फीट है। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1659 फीट है। इसके चलते डैम अभी भी साढ़े 10 फीट खाली है। बड़ा तालाब के गेट खुलने पर कलियासोत डैम में पानी आएगा और गेट खुल जाएंगे।

